



भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Accountant General (A&E)-II Uttar Pradesh, Prayagraj



पत्रांक- पेंशन विविध/17857, 16388, 11432, 16042 / 17204

दिनांक :- 24/03/2024

सेवा में,
निदेशक,
वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय,
जवाहर भवन, लखनऊ -226001

विषय :- अन्य राज्यों के राज्य कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान।

महोदय,

इस पत्र के साथ निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत सम्बन्धी शासनादेशों की प्रतियां प्रेषित कर रहा हूँ, जिसके अनुसार संबन्धित राज्य की पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि में मंहगाई राहत की दर एवं प्रभावी तिथि निम्नानुसार होगी :-

क्रमांक	राज्य का नाम	विषय / दर / प्रभावी तिथि	शासनादेश का सन्दर्भ
1	BIHAR	<p>1. - पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2023 के प्रभाव से 412% के स्थान पर 427% मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।</p> <p>2. - षष्ठम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2023 के प्रभाव से 221% के स्थान पर 230% मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।</p> <p>3. - सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2024 के प्रभाव से 46% के स्थान पर 50 % मंहगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।</p>	<p>GO.No. 3 ए-3-भत्ता-03/2022-2894/वि0, दिनांक 15/03/2024</p> <p>GO.No. 3 ए-3-भत्ता-02/2022-2893/वि0, दिनांक 15/03/2024</p> <p>G.O.No.- 3ए-3-भत्ता-01/2022-2892/वि0, दिनांक 15/03/2024</p>
2	CHHATTISGARH	छत्तीसगढ़ राज्य के सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01/01/2024 से मंहगाई राहत @50% करने के सम्बन्ध में। (46% से 50%)	F.No.- 2746/ 949/ 21- B/C/ G/2024, दिनांक 15/03/2024
3	GUJARAT	1. - Grant of Temporary Increase (Dearness Relief) to State Government Pensioners / Family Pensioners with effect from dated 01.07.2023 (7 th Pay Commission) (46%)	G.O No. HGV-102017-O-450-Pensioncell (P)

		2. - Grant of Temporary Increase (Dearness Relief) to State Government Pensioners / Family Pensioners with effect from 01.07.2023 (Revision of Pay Rule, 2009, 6 th Pay Commission) (230%)	Dated 15.03.2024 G.O No. HGV-102017-O-1201- Pensioncell (P) Dated 15.03.2024
4	TRIPURA	Grant of Dearness Relief to Central Government Pensioners/ family pensioners- Revised rate effective from 01.01.2024- reg. (46% to 50%)	G.O. No. 42/02/2024-P&PW (D), Dated 13.03.2024
5	RAJASTHAN	अन्य राज्यों से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे राजस्थान के उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियों (RHJS) की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन संशोधन हेतु।	G.O. No. F26 (55) Nyay/2015 part IV, Dated 12.03.2024

आपसे अनुरोध है कि संलग्न शासनादेशों में निहित निर्देशानुसार उक्त दरों से, संबन्धित राज्य के पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान देयता के आधार पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को भी सूचित करें। उक्त आदेशों की प्रति कोषागार के नोटिस बोर्ड में चस्पा करके व्यापक रूप से प्रचारित कर एवं अपने अधीनस्थ उप कोषागारों एवं बैंको को भी प्रति प्रेषित करें।

भवदीय

[Signature]
वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन

Dated :- 24/06/2024

No. Pension(Misc)/

Copy forwarded for information and necessary action to:-

SL.	Name of the Office & Address
1	Office of the Principal Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Path, Patna-800001
2	Office of The Principal Accountant General (A&E)-II, Chhattisgarh, Zero point Baloda Bazar Road, Raipur-492005
3	Office of The AG (A&E)- Gujarat, Ahemedabad, Audit Bhawan, 5 th Floor, Navarangpura Ahmedabad- 380009
4	Office of the Principal Accountant General (A&E), Tripura- Agartala-799006
5	AG(A&E) Rajasthan, 2, Jasnpath, "C" Scheme Jaipur-302005
6	Director of Treasuries, Jawahar Bhawan, 10 th Floor, Lucknow 226001 → 17207
7	All Chief Treasury Officer/Treasury Officer of the Uttar Pradesh. → 17212
8	Sr. Accounts Officer, O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Audit Bhawan, Vibhuti Khand, Gomatinagar, Lucknow-226010. → 17217
9	Dy. Accountant General (Pension) Cell Local.
10	Sr. Accounts Officer, Computer Cell, O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, 20 Sarojini Naidu Marg, Prayagraj-211001

[Signature]
सहायक लेखाधिकारी / पेंशन

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2024 के प्रभाव से 46% के स्थान पर 50% महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

A.G.B.
15 MAR 2024
PATNA

वित्त विभागीय संकल्प सं०-10441/वि० दिनांक-24/11/2023 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01/07/2023 के प्रभाव से 46% की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति दी गई

2. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/02/2024-P&PW(D), दिनांक-13/03/2024 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की दर 46% से बढ़ाकर 50% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

- सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2024 के प्रभाव से 46% के स्थान पर 50% महँगाई राहत की स्वीकृति दी जाती है।
- पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।
- महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता

पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन/पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

6. वर्धित महँगाई राहत के बकाये राशि का भुगतान मार्च माह के पेंशन सवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही महँगाई राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन महँगाई राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को वर्धित दर से महँगाई राहत, माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से भुगतेय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापक:-3ए-3-भत्ता-01/2022-2892/वि०

पटना, दिनांक:-15-03-2024

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/24

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

15/3/24

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2023 के प्रभाव से 221% के स्थान पर 230% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-6438/वि०, दिनांक-24.07.2023 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2023 के प्रभाव से 221% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/3(1)/2008-E.II(B), दिनांक-06.11.2023 द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2023 के प्रभाव से 221% से बढ़ाकर 230% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से कर रही है।

4. अतः समस्त विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-

(i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2023 के प्रभाव से 221% के स्थान पर 230% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग) के आधार पर महँगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

(iv) महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपय में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

(v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-2893/वि०

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक:- 15-03-2024

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

15/3/2024

संख्या-3ए-3-भत्ता-03/2022-...../वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2023 के प्रभाव से 412% के स्थान पर 427% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-6439, दिनांक-24.07.2023 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2023 के प्रभाव से 412% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/3(2)/2008-E.II(B), दिनांक-06.11.2023 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2023 के प्रभाव से 412% से बढ़ाकर 427% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-

(i) पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2023 के प्रभाव से 412% के स्थान पर 427% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से लागू पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई भत्ता की राशि को महँगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.07.2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 412% से बढ़ाकर 427% किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

(iii) पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महँगाई भत्ता/राहत परिगणित किया जायेगा,

Pen/18032401/257

le ver

किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

- (iv) महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- (v) उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-2894/वि०

पटना, दिनांक:-15-03-2024

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/04/24

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

15/3/2024



EC 336 8202924

SSDR/78
12/06/24

प्रति,

क्रमांक: पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्रा.पत्र./ 406

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

दिनांक: 30-05-2024

Date

1.	वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र.-5, कोषालय भवन, तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	110124
2.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा	520002
3.	O/o The Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh	791110
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी	781029
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, ऑडिट भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	380009
6.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार पटना, बीरचंद पटेल पथ, पटना	800001
7.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं-4, एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़	160047
8.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
9.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू काश्मीर, एग्जीक्यूटिव ग्राउंड के निकट, श्रीनगर	190009
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरेंडा, रांची	834002
11.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर	560001
12.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी.रोड, तिरुवनंतपुरम	695039
13.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)	474002
14.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मैरिन लाइन्स, मुम्बई	400020
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर	440001
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल	795001
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलांग	793001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, एजवल	796001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा	797001
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडिसा, भुवनेश्वर	751001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़	160017
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर	302005
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली, पी.ओ.-टाडोंग, गंगटोक	737102

जीरो पॉइन्ट, बलौदा बाजार रोड, रायपुर - 492005, दूरभाष : +91-771-2285954, पी.बी.एक्स : 2281451, फैक्स : +91-771-2282607
 ZERO POINT, BALODA BAZAR ROAD, RAIPUR-492005 Tel.: +91-2285954, P.B.X. : 2281451, Fax : +91-771 - 2282607
 ई-मेल / E-mail : agChattisgarh@cag.gov.in, agaechhattisgarh@cag.gov.in



Scanned with OKEN Scanner

E-1895811

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT, MANTRALAYA
MAHANADI BHAWAN,
NAVA RAIPUR, ATAL NAGAR, (C.G.) 492002

// ORDER //

Raipur/03/2024

F.No. 2746/949/21-B/C.G./2024, the State Government, consequent to the enhancement of the rate of Dearness Allowance payable to the Central Government officers/employees vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure O.M. No. 1/1/2024-E-II (B), dated 12.03.2024, hereby, enhances the Dearness Allowance payable to the Judicial Officers of the State, whose pay scale have been revised on the basis of 2nd National Judicial Pay Commission recommendation including on the basis of 7th Pay Commission (Interim) and/or to Pensioner Judicial Officers and to Family Pensioners of Deceased Judicial Officers of the State, who are receiving pension/ family pension as per revised pay scale, from the existing rate of 46% to 50% w.e.f. 01.01.2024.

By Order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(Rajnish Shrivastava)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Law & Legislative Affairs Department

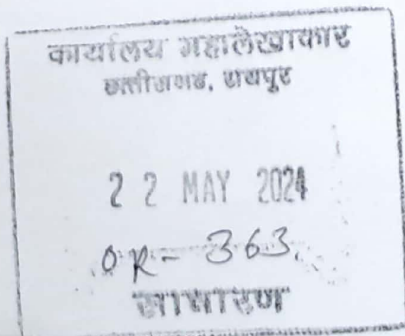
20
275.4
2747
Endt. No. /949 /21-B/C.G./2024

Raipur,/03/2024

Copy to:

1. Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur,
2. Secretary, Government of Chhattisgarh, Finance Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar,
3. Secretary, General Administration Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar,
4. Accountant General, Chhattisgarh, Raipur,
5. Legal Advisor to Governor, Governor's Secretariat, Raipur,
6. Director, Treasury, Accounts and Pension, Raipur,

Continued..2..



D/Judicial Branch/BK.J.Letter - 1741



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) गुजरात, अहमदाबाद
 'ऑडिट भवन', पौचवी मंजिल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद — 380009

Phone: - (079) 2640 1282, 2640 1382, Fax No. (079) 2644 8455, E-Mail ID: - braeahmedabad@cag.gov.in ag-ahmd-guj@nic.in

सं/पेशन/जी. आर./विशेषमुद्रा/G.O.G.01& 02/DA/DR/2024-25/जा. सं. 201 दिनांक:-28/05/2024

विषय:- Grant of Temporary Increase (Dearness Relief) to Gujarat State Government Pensioners/Family Pensioners With effect from 01/07/2023.

क्र. सं.	जा. सं.	कार्यालय का नाम एवं पता	क्र. सं.	जा. सं.	कार्यालय का नाम एवं पता
1	170	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा -520002	17	186	कार्यालय महालेखाकार, (लेखा एवं हक)-II, उत्तर प्रदेश, ऑडिट भवन, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ - 226010
2	171	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), मेघालय, शिलांग-793 001	18	187	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), पश्चिम बंगाल, कलकत्ता-700 001
3	172	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), आसाम, Maidamgaon, Beltola गुवाहाटी-781 029	19	188	महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक), जम्मू - कश्मीर, श्रीनगर -190 009
4	173	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) -I, झारखंड रांची- 834 002	20	189	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), मणीपुर, इम्फाल-795 001
5	174	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक)-II, बिहार, गांधी मैदान, पटना -800 00	21	190	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), त्रिपुरा, अगरतला - 799 006
6	175	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), एम.जी.रोड, डाक थैला सं 5607, तिरुवनन्तपुरम- 695 001, केरल	22	191	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), नागालैण्ड, कोहीमा-797 001
7	176	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), मध्यप्रदेश, ग्वालीपर-474 002	23	192	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) उत्तराखंड, कौलागढ़, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248 195.
8	177	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) तमिलनाडू, 361, अत्रा सलाई, चेन्नई-600018	24	193	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), छत्तीसगढ़, जीरो पॉइंट बलौदा बाजार रोड, पो. मांडर रायपुर-493111
9	178	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) -I, महर्षि कर्वे मार्ग, महाराष्ट्र, मुंबई- 400 020	25	194	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), मिजोरम, नई कैपिटल परिसर, खातला, आइज़ोल-796 001
10	179	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) -II, वेस्ट हाईकोर्ट रोड, महाराष्ट्र नागपुर -440 001	26	195	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), सिक्कीम, गंगटोक -737 102
11	180	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), कर्नाटक, बेंगलुरु - 560 001	27	196	कार्यालय वेतन एवं लेखा अधिकारी, 5 पेंशन, दिल्ली, तीस हजारी, नई दिल्ली-110 054
12	181	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), उड़ीशा, भुवनेश्वर -751 001	28	197	लेखा नियंत्रक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली -110 001
13	182	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), पंजाब, चंडीगढ़, सेक्टर -17, पिन -160 017	29	198	निदेशक, लेखा एवं कोषागार कार्यालय, गोवा सरकार, गोवा, पणजी- 403 001
14	183	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), हरियाणा, सेक्टर- 33/बी, प्लॉट-नं- 4 & 5, चंडीगढ़-160 047	30	199	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (संघ क्षेत्र), डी. ए. टी. रोड, राइनबो नगर D.A.T. Road, Rainbow nagar, पॉडिचेरी-605 001
15	184	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), हिमाचल प्रदेश, गार्टन कैसल वीलडिंग, शिमला- 171 001	31	200	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन, अरुणाचल प्रदेश, नहरलागुन - 791 110 (Naharlagun) Arunachal Pradesh
16	185	महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हक) भगवानदास रोड राजस्थान, जयपुर-302005.	32	201	कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक)-II, उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाथ मार्ग, प्रयागराज - 211001 उत्तर प्रदेश;

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक)
 अहमदाबाद, गुजरात

16388
 5/6/24

Pen (misc)

04 JUN 2024

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) गुजरात, अहमदाबाद
'ऑडिट भवन', पाँचवी मंजिल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद — 380009
Phone: - (079) 2640 1282, 2640 1382, Fax No. (079) 2644 8455,
E-Mail ID: - braeahmedabad@cag.gov.in ag-ahmd-guj@nic.in

सं.पेंशन/जी.आर./विशेषमुद्रा/G.O.G.01 & 02/DA/DR/2024-25/ जा. सं.

दिनांक:- 28/05/2024.

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय।
(सूची अनुसार)

विषय:-

- (1) Grant of Temporary Increase (Dearness Relief) to Gujarat State Government Pensioners / Family Pensioners with effect from Dated: 01/07/2023 (Admissible Rate 46% of the Basic pay) as per the 7th Pay Commission.
- (2) Grant of Temporary Increase (Dearness Relief) to Gujarat State Government Pensioners/ Family Pensioners with effect from Dated: 01/07/2023 (Admissible Rate 230% of the Basic pay) as per the Revision of Pay Rule, 2009, 6th Pay Commission.

संदर्भ:- (1) Govt. Of Gujarat, Finance Department, GR No. HGV-102017-O-450- PENSION CELL (P)
Dated:-15/03/2024.(2) Govt. Of Gujarat, Finance Department, GR No HGV-102017-O-1201- PENSION CELL (P)
Dated:- 15/03/2024.

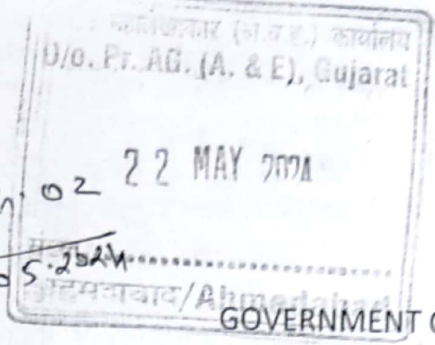
महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में वित्त मंत्रालय, गुजरात सरकार के संकल्प पत्र संदर्भ 01 & 02 आपको प्रेषित किया जा रहा है। आप से अनुरोध है की आप इसे अपने राज्य के सभी कोषागारों/पेंशन भुगतान प्राधिकारियों को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि आपके राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहे गुजरात राज्य के सभी पेंशनरों/पारिवारिक को इसका त्वरित लाभ मिल सके। कृपया पत्र की पावती भेजे एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करें।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन



Grant of Temporary Increase
(Dearness Relief) to State
Government Pensioners/
Family Pensioners with effect
from dated: 01/07/2023
(7th Pay Commission)

GOVERNMENT OF GUJARAT
Finance Department
Govt. Resolution No. HGV-102017-O-450-Pensioncell (P)
Sachivalaya, Gandhinagar.
Dated: 15/03/2024

Read:-

- (I) GR FD No.PGR-102016-6-Pay Cell, Dated: 15/10/2016.
- (II) GR FD No. PGR-102016-7-Pay Cell, Dated: 15/10/2016.
- (III) GR FD NO. HGV-102017-O-450-P, Dated: 20/08/2022.
- (IV) Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure
O.M.No.1/4/2023-E-II(B), Dated: 20/10/2023.
- (V) GR FD NO. VLB-102016-GOI-7-CH, Dated: 29/02/2024.

RESOLUTION

The State Government has decided to pay 42% Temporary Increase (Dearness Relief) to State Government Pensioners/Family Pensioners vide GR mentioned at (III) above. Government has now decided to increase the rates of Temporary Increase (Dearness Relief) admissible to State Government Pensioners/ Family Pensioners with effect from Dt.01/07/2023 as under.

No.	Admissible from date	Admissible Rate
1.	From 01/07/2023	46% of the basic pay

1. Payment of Temporary Increase (Dearness Relief) involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee (lower or higher).
2. Temporary Increase (Dearness Relief) at the rates indicated in above table will also be admissible on the additional basic pension/additional family pension available to Pensioners/Family Pensioners based on their age as indicated in Government Resolution, Finance Department, No.PGR-102016-6-Pay Cell, dated 15th October, 2016 and Government Resolution, Finance Department No. PGR-102016-7-Pay Cell, dated 15th October 2016.
3. The Temporary Increase as 46% will be paid regularly along with monthly pension from March-2024, the difference of months from July-2023 to February-2024 of the proposed Temporary Increase will be paid in Three installments: (1) First installment (July-2023 to September-2023) along with the pension of March-2024 (paid in April-2024) (2) Second installment (October-2023 to December-2023) along with the pension of April-2024 (paid in May-

2024 (3) Third installment (January-2024 to February-2024) along with pension of May-2024 (paid in June-2024).

4. It will be the responsibility of the Pension Disbursing Authority to calculate the quantum of Dearness Relief payable in each individual case.
5. All Accountant General of the respective States/Central Administrative Authority except Gujarat State are requested to take necessary action to authorize all the disbursing authorities under their control for making payment to Gujarat Pensioners drawing pension from their State Treasuries, including Public Sector Banks.
6. Other Provisions governing grant of temporary Increase (Dearness Relief) to Pensioners such as regulations of dearness relief during employment/re-employment, regulations to temporary increase (Dearness Relief), where more than one pension is drawn etc. will remain unchanged.

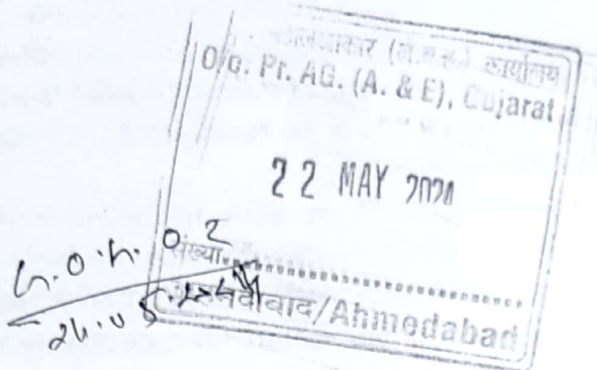
By order and in the name of the Governor of Gujarat.


(Bhavita Rathod)
Deputy Secretary
Finance Department

To,

- The Principal Secretary to the Hon'ble Governor, Rajbhavan, Gandhinagar
- The Chief Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Gandhinagar
- The Personal Secretaries to all Hon'ble Ministers/State level Ministers
- The Secretary, Gujarat Legislative Secretariat, Gandhinagar
- The Secretary, Gujarat Vigilance Commission, Gandhinagar
- The Secretary, Gujarat Civil Service Tribunal, Gandhinagar
- The Secretary, Hon'ble Gujarat High Court, Ahmedabad
- The Secretary, Gujarat Subordinate Staff Selection Board, Gandhinagar
- The Secretary, Gujarat Public Service Commission, Ahmedabad
- All Departments of Secretariat/All HoDs/All Head of Offices
- The Accountant General-I (Audit), Gujarat State, Ahmedabad/Rajkot
- The Accountant General-11 (A&E), Gujarat State, Ahmedabad/Rajkot
- The Examiner, Local Fund Accounts /All Dist. Assistant Examiners
- All District Collectors/District Development Officers
- The Director, Pension & Provident Fund, Gandhinagar
- The Pension Payment Office, Ahmedabad
- All District Treasury Officers/Sub Treasury Officers
- The Pay and Accounts Officer, Gandhinagar/Ahmedabad
- The Pay and Accounts Officer, SSNNL, Gandhinagar/Vadodara
- The Resident Audit Officer, Gandhinagar/Ahmedabad
- All Boards/Corporations/Universities /Public Sector Undertakings of the Government,
- All Officers/branches in Finance Department
- All recognized Associations
- The System Manager, Finance Department - For placing on the website.
- Select file, Pay Cell, M, Ch, P, A & Z br., Finance Department, Sachivalaya, Gandhinagar

By letter



GOVERNMENT OF GUJARAT

Finance Department

Govt. Resolution No. HGV-102017-O-1201-Pensioncell (P)

Sachivalaya, Gandhinagar.

Dated: 15/03/2024

Read:-

- (I) GR FD No. PGR-1009-6 & 7-Pay Cell (M), Dated: 27/02/2009.
- (II) GR FD No. PGR-102009-4 & 5-Pay Cell, Dated: 13/04/2009.
- (III) GR FD No. HGV-102017-O-1201-P, Dated: 31/05/2023.
- (IV) Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure O.M.No.1/3(1)/2008-E.II(B), Dated: 06/11/2023.
- (V) GR FD NO. VLB-102009-GOI-10-CH, Dated: 29/02/2024.

RESOLUTION

The Pensioners/Family Pensioners who are getting pension/family pension according to Pay Scale of G.C.S.R. (Revision of pay), Rule 2009 (6th Pay Commission) have been accorded Temporary Increase (T.I.) up to 221% vide Government Resolution as mentioned at (III) above.

Now, the State Government has decided to increase the rates of Temporary Increase (Dearness Relief) admissible to State Government pensioners/family pensioners, who are getting pension/family pension according to Revision of Pay Rules, 2009 (6th Pay Commission) as under.

No.	Admissible from date	Admissible Rate
1.	From 01/07/2023	230% of the basic pay

1. Payment of Temporary Increase (Dearness Relief) involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee (lower or higher).
2. Temporary Increase (Dearness Relief) at the rates indicated in above table will also be admissible on the additional basic pension/additional family pension available to Pensioners/Family Pensioners based on their age as indicated in Government Resolution, Finance Department, No. PGR-1009-4 & 5-Pay Cell, Dated : 13/04/2009 and Government Resolution, Finance Department No. PGR-102016-6-Pay Cell, Dated : 15/10/2016.
3. The Temporary Increase as 230% will be paid regularly along with monthly pension from March-2024, the difference of months from July-2023 to

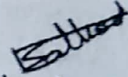
February-2024 of the proposed Temporary Increase will be paid in installments: (1) First installment (July-2023 to September-2023) along with the pension of March-2024 (paid in April-2024) (2) Second installment (October-2023 to December-2023) along with the pension of April-2024 (paid in January-2024) (3) Third installment (January-2024 to February-2024) along with the pension of May-2024 (paid in June-2024).

4. It will be the responsibility of the Pension Disbursing Authority, to calculate the quantum of Dearness Relief payable in each individual case.

5. All Accountant General of the respective States/Central Administrative Authority except Gujarat State are requested to take necessary action to authorize all the disbursing authorities under their control for making payment to Gujarat Pensioners drawing pension from their State Treasuries, including Public Sector Banks.

6. Other Provisions governing grant of temporary Increase (Dearness Relief) to Pensioners such as regulations of dearness relief during employment/re-employment, regulations to temporary increase (Dearness Relief), where more than one pension is drawn etc. will remain unchanged.

By order and in the name of the Governor of Gujarat.


(Bhavita Rathod)
Deputy Secretary
Finance Department

To,

- The Principal Secretary to the Hon'ble Governor, Rajbhavan, Gandhinagar
- The Chief Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Gandhinagar
- The Personal Secretaries to all Hon'ble Ministers/State level Ministers
- The Secretary, Gujarat Legislative Secretariat, Gandhinagar
- The Secretary, Gujarat Vigilance Commission, Gandhinagar
- The Secretary, Gujarat Civil Service Tribunal, Gandhinagar
- The Secretary, Hon'ble Gujarat High Court, Ahmedabad
- The Secretary, Gujarat Subordinate Staff Selection Board, Gandhinagar
- The Secretary, Gujarat Public Service Commission, Ahmedabad
- All Departments of Secretariat/All HoDs/All Head of Offices
- The Accountant General-I (Audit), Gujarat State, Ahmedabad/Rajkot
- The Accountant General-11 (A&E), Gujarat State, Ahmedabad /Rajkot
- The Examiner, Local Fund Accounts /All Dist. Assistant Examiners
- All District Collectors/District Development Officers
- The Director, Pension & Provident Fund, Gandhinagar
- The Pension Payment Office, Ahmedabad
- All District Treasury Officers/Sub Treasury Officers
- The Pay and Accounts Officer, Gandhinagar/Ahmedabad
- The Pay and Accounts Officer, SSNNL, Gandhinagar/Vadodara
- The Resident Audit Officer, Gandhinagar/Ahmedabad
- All Boards/Corporations/Universities /Public Sector Undertakings of the Government,
- All Officers/branches in Finance Department
- All recognized Associations
- The System Manager, Finance Department - For placing on the website.

ER 385130656 ZM

स्पीड पोस्ट



क्रमांक:- पेंशन प्राधि./आदेश/के-107/2024-25/610

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date: 28/5/24

प्रधान महालेखाकार (लेखा),
20 सरोवरी नाथपूर मण्डल,
जयपुर, उत्तर प्रदेश-211001

विषय:- अन्य राज्यों से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे राजस्थान उच्च न्यायालय के
सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (RHJS) की पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन हेतु।
संदर्भ:-कानून एवं कानूनी कार्य विभाग, राजस्थान सरकार का आदेश क्रमांक
F26(55)Nyay/2015partIV dt. 12.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के क्रम में निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक निपेवि/सीपीडीएमसी/आउटसाईड/2023/1764 दिनांक 08.05.2024
प्राप्त हुआ है (प्रति संलग्न)। उसमें उल्लेख किया गया है कि अन्य राज्यों से पेंशन/पारिवारिक पेंशन
प्राप्त कर रहे राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (RHJS) की पेंशन/पारिवारिक
पेंशन ले रहे पेंशनर्स के भत्तों में उक्त संदर्भित आदेश के अनुसार संशोधन किया जाना है।

अतः आप से निवेदन है कि आपके राज्य में स्थित सभी कोषालयों को उपरोक्त आदेशानुसार
निर्देश प्रदान कर पावती इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करावें।

उक्त कार्य को प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार
(भत्तों के आदेश की कोपी)

भवदीय

वरि.लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि.



16042
4106/24

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.)-II,
जयपुर, राजस्थान

Pen (misc)

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष : (0141)2385431-39, फ़ैक्स: (0141)2385263

Janpath, Jaipur- 302005, Tel.: (0141)2385431-39, Fax : (0141) 2385263

ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in



Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005

ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभाष नं. 0141-2740538, 2741687
वेबसाइट :- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक:-निपेवि/सीपीडीएमसी/आउटसाईड/ 2023 / 1764

दि. 08.05.2024

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक),
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक),
राजस्थान, जयपुर

विषय:- अन्य राज्यों से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे राजस्थान के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त
न्यायिक अधिकारियों (RHJS)की पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन हेतु।
संदर्भ:- कानून एवं कानूनी कार्य विभाग, राजस्थान सरकार का आदेश क्रमांक F26(55)Nyay/2015part
IV Dated 12.03.2024

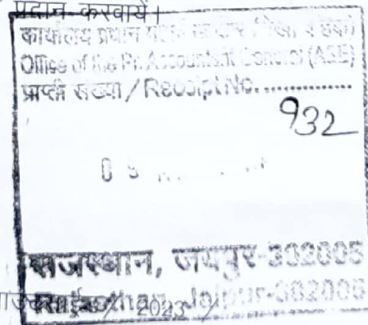
महोदय,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (Civil) No. 643/2015, All India Judges
Association vs Union of India में दिए गए निर्णय के अनुरूप Second National Judicial Pay
Commission (SNJPC) की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन, पेंशन एवं भत्तों के
संशोधन हेतु केबिनेट आदेश क्रमांक 17/2024 दि. 11.03.2024 के अनुसरण में कानून एवं कानूनी
कार्य विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F26(55)Nyay/ 2015 part IV Dated 12.03.2024
की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि अन्य राज्यों से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे राजस्थान के
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (RHJS)की पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर देय भत्ते
संशोधित किए जाने है।

अतः आप से निवेदन है कि समस्त राज्यों में स्थित प्रधान महालेखाकार (हक एवं लेखा) कार्यालयों को
संदर्भित आदेश के अनुरूप संबंधित बैंक शाखा/ कोषालय स्तर पर उपरोक्त संशोधन करवाने का निर्देश
प्रदान कर अनुग्राहित करावें।

कृपया उक्त कार्य को प्राथमिकता प्रदान करवायें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



भवदीय,

(डॉ० देवराज)
निदेशक

दि.

क्रमांक:-निपेवि/सीपीडीएमसी/आउटसाईड/ 2023 / 1764

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त निदेशक, पीजीआरसी/पीसी/नियम, कार्यालय हाजा,
2. संयुक्त निदेशक (आईटी), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवायें।
महालेखाकार (लेखा एवं हक), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान
को ईमेल करवाने हेतु।

Signature valid

Digitally signed by Devraj
Designation: Director
Date: 2024.05.04 23:08:14 IST
Reason: Approved
(अतिरिक्त निदेशक)
मुख्यालय

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

No.F. 26(55) Nyay / 2015 part IV

Dated 12.03.2024

ORDER

Pursuant to the Judgement dated 04.01.2024, passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 643/2015, *All India Judges Association vs Union of India* on the recommendations of Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) relating to the revision of pay, pension and allowances to the Judicial Officers, and pursuant to Cabinet Order No. **17/2024** dated **11.03.2024**, the Governor of Rajasthan is pleased to issue following orders:-

1. House Building Advance (HBA):-

- (i) HBA shall be made available to judicial officers in terms of the House Building Advance Rules, 2017; and
- (ii) HBA shall be available to judicial officers also for the purchase of a ready built house from private individuals subject to such safeguards as may be prescribed by the State Government in consultation with Rajasthan High Court.

2. Children Education Allowance (CEA):-

The Children Education Allowance shall be available to the judicial officers at the following rates:-

- (a) Rs 2,250 per month as CEA and Rs 6,750 per month as hostel subsidy for two children up to Class 12;
- (b) For children with special needs, the reimbursement would be at double the rate stated in (a);
- (c) When the DA increases by 50%, the allowances and subsidy shall be increased by 25%;
- (d) The rights of officers who are already receiving this benefit will not be adversely affected by the recommendation; and
- (e) This allowance shall be available w.e.f. 01.04.2019.



3. City Compensatory Allowance (CCA):-

CCA shall be discontinued w.e.f. 1st March, 2024.

4. Concurrent Charges Allowance:-

In partial modification of order No. F.11(3)Nyay/2002, dated 08.09.2005 of this Department, the following order is made:-

1. The concurrent charge allowance shall be available maximum at the rate of 10% of the minimum of the scale of the additional post held beyond a period of ten working days.
2. No upward revision in the percentage of the Concurrent Charge allowance.
3. High Court shall decide the Concurrent Charge allowance to be available to the Officer within the ceiling of 10% on the basis of the number of days worked, the quantum of judicial work turned out and the administrative work handled.
4. The criterion laid down by FNJPC be dispensed with and there shall not be any insistence on the performance of 'appreciable judicial work' of the Court concerned.

5. Dearness Allowance:-

Dearness Allowance shall be paid at the rate fixed by the Central Government.

6. Earned Leave Encashment:-

In continuation and partial modification of order No. F. 11(3) Nyay/2002, dated 08.08.2005 issued by this Department, the following order is made:-

1. No enhancement in the maximum limit of 300 days leave encashment at the time of retirement.
2. A judicial officer shall be entitled to encash:-



- (a) 10 days earned leave while availing LTC subject to maximum 60 days – 10 earned leave at a time up to six occasions during the entire service.

A judicial officer shall be entitled to encash 10 days earned leave for each LTC availed by him from the existing block year of 2015-2019 and onwards except the extended LTC availed after 01.01.2016.

- (b) 30 days in a block of two years.
(c) S.No.(a) and (b) shall be in addition to the right of the Judicial Officers to encash up to 300 days EL at the time of retirement.

3. In case of officers who have retired and while granting leave encashment at the time of retirement, the leave encashment availed during service stand adjusted, shall be paid the amount of the so adjusted earned leave, at the time of retirement, within a period of three months from the date of acceptance of the report.

7. Higher Qualification Allowance:-

In partial modification of order No. F.11(3) Judl/2002, dated 07.05.2003 issued by this Department, the following order is made:-

1. The Judicial Officers shall be granted three advance increments for acquiring higher qualification i.e. post-graduation in law and one more advance increment if he acquires Doctorate in Law.
2. The advance increments once granted for post-graduation degree or Doctorate in law shall not be granted again if, in future, the officer acquires post graduate or Doctorate degree in any other subject.
3. The advance increments shall be available to the officer who had acquired the post-graduation degree or Doctorate either before recruitment or at any time subsequent thereto while in service.



4. The advance increments shall be granted from the date of initial recruitment, if the officer has already acquired the post-graduation degree or Doctorate and from the date of acquiring the post-graduation or Doctorate degree, if acquired after joining the service.
5. The advance increments shall be available to the officers if the higher-qualification has been acquired through regular studies as well as distant learning programmes.
6. The advance increment shall be available when the Officer is promoted from Civil Judge to Senior Civil Judge and from Senior Civil Judge to District Judge cadre also at ACP stage.
7. The advance increments shall be available in the District Judge Cadre from District Judge (Entry Level) to District Judge (Selection Grade) and from District Judge (Selection Grade) to District Judge (Super Time Scale).
8. The advance increments for all practical purposes shall be part of salary and Dearness Allowance shall be available on the same.
9. The discontinued benefit of advance increments for higher educational qualification may be restored from 01.01.2016 in accordance with SNJPC recommendations and pay shall be revised accordingly without any notional benefit.

8. Hill Area/ Tough Location Allowance:-

1. Hill Area/Tough Location Allowance @Rs.5000/- per month shall be paid to the Judicial Officers posted in hill areas/tough locations.
2. Hill areas/Tough locations will be specified by the Rajasthan High Court.
3. This allowance shall be available w.e.f. 01.01.2016.

9. Home Orderly/ Domestic Help Allowance:-

1. The Home-cum-office orderly allowance shall be available to the serving Judicial officers at the following rates w.e.f. 01.01.2020 :-



- (i) District Judges : minimum wages of one unskilled worker in the State subject to minimum of Rs.10,000/- per month.
- (ii) Senior Civil Judges and Civil Judges : 60% of the minimum wages of one unskilled worker in the State subject to minimum of Rs.7,500/- per month.
- (iii) The Home Orderly Allowance for serving Judicial Officers shall stand increased by 5% on yearly basis from 01.01.2020.

2. In continuation and partial modification of order No. F.26(12) Nyay/2009 dated 03.05.2010 issued by Department of Law and Legal Affairs, Rajasthan Government, Domestic Help Allowance to the pensioners and family pensioners shall be available at the following rates from 01.01.2016:-

- (a) (i) Pensioner : Rs.9,000/- per month.
- (ii) Family pensioners : Rs.7,500/- per month.
- (b) For pensioners and family pensioners this allowance shall stand increased by 30% on completion of five years from 01.01.2016 that is, w.e.f. 01.01.2021, i.e. Rs 11700 and Rs 9750 respectively from 01.01.2021.

10. House Rent Allowance:-

HRA:-

In continuation and partial modification of order No. F.26(55) Judl/2015 dated 27.12.2022 issued by this Department, the following order is made:-

- (i) Judicial officers who are allotted official quarters for residence shall not be entitled to HRA;
- (ii) Judicial officers residing in their own houses, including the house of a parent or spouse, shall be entitled for the recommended HRA with effect from 01.01.2016 after obtaining permission from the High Court to reside in their own house and judicial officers already residing in hired accommodation will be entitled to the recommended HRA with effect from 01.01.2020, subject to the actual rent paid within the said ceiling;



- (iii) The Office of the Principal District Judge or equivalent shall pay rent directly to the landlord, in such case, the officer is not eligible to draw HRA; and
- (iv) The SNJPC rates of HRA should be applicable to all Judicial Officers as per the notification dated 07.07.2017 which was issued after the 7th Central Pay Commission (CPC) by the Central Government:-

Classification Of Cities	Rates of HRA/PM as percent of basic pay
X	24%
Y	16%
Z	8%

However, the minimum rates prescribed are 5400/-, 3600/- and 1800/- respectively and the rate will be changed in accordance with the change in Dearness Allowance in the following terms:-

Classification Of Cities	Rates of HRA/PM as percent of basic pay	When DA Crosses
X	27%	25%
	30%	50%
Y	18%	25%
	20%	50%
Z	9%	25%
	10%	50%

The High Court is at liberty to upgrade and add the cities in different classes.

2/11/17

Furniture & Air Conditioner Allowance:-

In continuation and partial modification of order No. F.11(03)/Nyay/2002 dated 10.11.2015 issued by this Department, the following order is made:-

1. Furniture grant of Rs.1.25 lakhs every five years shall be provided to the Judicial Officer subject to production of proof of purchase.
2. Household electrical appliances can also be purchased by availing of the said grant.
3. The Officers having not less than two years of service shall also be eligible for this allowance.
4. The option to purchase the furniture being used by the officer at the depreciated rate shall be available at the time of fresh grant or retirement.
5. Apart from the furniture grant, one air-conditioner shall be provided at the residence of every Judicial Officer once in every five years. Judicial Officer may purchase one Air Conditioner up to Rs. 75,000/ every five years (block 2016-2020, 2021-2025 and so on).
6. The five yearly block period regarding Furniture Grant and Air-Conditioner is re-determined as Calendar Year 2016-2020 and so on.
7. The condition of retaining the furniture at depreciated value has to be followed but this condition shall not apply for items already purchased under existing grant and consumable articles. Condition of retention at depreciated value shall be applied with prospective effect. The condition of retaining at depreciated value shall not apply to the Air-Conditioner.
8. Furniture grant is admitted on five yearly block period. The First block for Furniture Grant shall commence from 01.01.2016 up to 31.12.2020 (Calendar years) and so on.
9. Furniture Grant issued during the block of 2015-2019 will be adjusted against the first block of 2016-2020. If any judicial



officer has received the second grant thereafter, the same shall be adjusted against the second block of 2021-2025.

10. Arrears of Furniture Grant shall be admissible subject to the stipulation that Judicial Officers will submit the proof of utilisation and payment.

11. Any officer who had already purchased furniture and reimbursed according to existing provisions, shall be reimbursed the differential amount subject to following conditions:-

(i) he had already submitted the vouchers and receipts of purchase of furniture; and

(ii) the maximum amount to be reimbursed shall not exceed the limit of Rs. 1.25 lakhs or the actual amount paid, whichever is less.

11. Leave Travel Concession (LTC)/ Home Travel Concession (HTC):-

In continuation and partial modification of order No. F.26(12) Nyay/2009 dated 24.02.2011 issued by this Department, the following order is made:-

(i) Encashment of 10 days earned leave while availing LTC (not HTC) (subject to the maximum of 60 days) shall be available. The same will be in addition to encashment of 300 days at the time of retirement and 30 days in a block of two years.

(ii) (a) The Judicial Officers shall be permitted to avail one LTC and one HTC in a block of 3 years.

(b) As far as fresh recruits are concerned, the HTC shall be allowed 2 times in the first block of 3 years. However, the block of 3 years will commence on completion of the period prescribed for probation (not necessarily declared).

(iii) (a) The Judicial officers, irrespective of their rank, shall be allowed to travel by air and the reimbursement shall be made subject to the condition that the tickets have been purchased either directly from the Airlines or from the agents authorized, namely, Ashoka Travels, Balmer and Lawrie and IRCTC by the Central/State



Government subject to further addition or deletion of the authorized agent by the Central/State Government.

(b) The other details such as class of travel, advance etc. shall be governed by the respective Rules/Orders of the State.

(iv) The Judicial officers shall be allowed to carry forward LTC anywhere in India beyond retirement for a period of one year.

(v) The LTC/HTC facility shall not be available to the retired judicial officers.

(vi) The Judicial officers shall not be required to avail of earned leave only for LTC/HTC purpose and they may be permitted to avail of casual leave as a prefix and suffix to the extent of two days.

Note:- Block Year for LTC/HTC will commence from 01/01/16 and blocks of year will be redetermined accordingly as 2016-2018, 2019-2021, 2022-2024 and so on.

The block year 01/11/2015-31/10/2019 is redetermined as 01/01/16-31/12/2018 and similarly the block year 01/11/2019-31/10/2023 is redetermined as 01/01/2019-31/12/2021 and so on.

The present block period for LTC/HTC shall exist only up to 31.12.2024.

12. Medical Allowance/ Medical Facilities:-

In compliance of the judgement of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 643/2015, *All India Judges Association vs Union of India* dated 04.01.24, the following order is made:-

- (i) Fixed medical allowance shall be payable at the rate of Rs.3,000/- per month to the serving Judicial Officers, with effect from 01.01.2016, instead of Rs 1000 as payable under Rule 8 of Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) Rules, 2008;
- (ii) Fixed medical allowance shall be payable at the rate of Rs.4,000/- per month to the pensioners and family pensioners, with effect from 01.01.2016, instead of Rs 1500 as payable to



pensioners under Rule 8 of Rajasthan Judicial Officers (Medical Facilities) Rules, 2008;

- (iii) The spouse or other dependents of Judicial Officers drawing family pension shall also be eligible for medical facilities/ reimbursement at par with the pensioners of the judiciary; and
- (iv) Other substantive recommendations of SNJPC regarding Medical facilities and reimbursement of medical expenses are also accepted but detailed orders/consequential amendments in the said Rules of 2008 shall be issued/made subsequently.

13. Newspaper and Magazine Allowance :-

In continuation and partial modification of order No. F.11(3) Nyay/02 part, dated 08.09.2005 issued by this Department, the following order is made:-

1. Reimbursement for newspaper and magazines shall be Rs.1000/- per month for District Judges (two newspapers and two magazines) and Rs.700/- per month for Senior Civil Judges and Civil Judges (two newspapers and one magazine).
2. The reimbursement shall be on half yearly basis from January to June and July to December, on the basis of self certification.
3. The allowance at the above mentioned rates shall be available from 01.01.2020.

14. Robe Allowance:-

In continuation and partial modification of order No. F.26(12) Nyay/2009 part, dated 24.02.2011 issued by this Department, the following order is made:-

- (i) An allowance of Rs. 12,000 will be payable once in three years with effect from 01.01.2016; and
- (ii) The block period for Robe Allowance is re-determined as Calendar year 2016-2018, 2019-2021, 2022-2024 and so on.

15. Special Pay for Administrative Work:-

1. Special Pay for Judicial officers doing administrative work shall be payable to all the judicial officers at the following rate:



- (a) Principal District and Sessions Judges (Present/Previous):
Rs.7000/- per month;
- (b) Other District Judges including 1 Additional District
Judges: Rs. 3500/- per month;
- (c) District Judges presiding over Special Courts and
Tribunals having independent administrative
responsibilities: Rs.3500/- per month; and
- (d) Senior Civil Judges and Civil Judges:
Rs.2000/- per month.

2. The Special Pay shall be available w.e.f. 01.01.2019.

16. Sumptuary Allowance:-

In partial modification of order No. F.26(12) Nyay/2009 part, dated 03.05.2010 issued by this Department, the following order is made:-

1. The sumptuary allowance to the Judicial Officers shall be revised as under w.e.f. 01.01.2016 :-

District Judges	Rs. 7,800/- per month
Senior Civil Judges	Rs. 5,800/- per month
Civil Judges	Rs. 3,800/- per month

2. The following categories of Judicial Officers shall get Rs.1,000/- (One thousand) per month more by virtue of their status or the additional responsibilities they shoulder:-

- Principal District Judge in-charge of administration in the Districts/Cities.
- District Judges in Selection Grade and Super Time-scale.
- Director of Judicial Academy/Judicial Training Institute/Member Secretary, State Legal Services Authority.
- Chief Judicial Magistrate/Chief Metropolitan Magistrate.

3. No sumptuary allowance shall be payable to retired Judicial Officers.



17. Transfer Grant:-

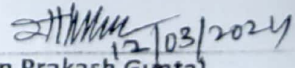
In continuation and partial modification of order No. F.11(3) Nyay/2002, dated 05.07.2006 issued by this Department, the following order is made:-

1. On transfer, the composite transfer grant shall be equivalent to one month's basic pay.
2. If the transfer is to a place at a distance of 20 kilometers or less or within the same city (if it involves actual change of residence), the transfer grant shall be 1/3rd of the basic pay.
3. For the transportation of personal effects, the O.M. dated 13.07.2017 (annexed as Appendix I) issued by the Department of Expenditure, Government of India pursuant to the recommendations of VII CPC shall apply.
4. In case of transportation by road, the admissible amount shall be Rs.50/- per km. inclusive of labour charges for loading and unloading or the actual whichever is lower. The said amount shall be raised by 25% when the DA increases by 50%.
5. The recommendations will come into effect from 01.01.2016.
6. The Officers who have undergone transfer(s) after 01.01.2016 and their claims for transfer grant paid as per pre-revised pay scales, shall be paid the differential amount on the basis of revised pay w.e.f. 01.01.2016.

The amount already drawn as per existing provisions shall be reduced from the revised amount.

This order is being issued in accordance with the concurrence of the Finance Department vide I.D. No. 192400029 Dated 22.02.2024.

By Order of the Governor


(Gyan Prakash Gupta)

Principal Secretary

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
- 2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान ।
- 3 निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर।
- 8 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
- 9 वित्त (नियम/बजट/व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 11 रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 12 समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
- 13 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. समस्त जिला कोषाधिकारी, राजस्थान।
- 17 प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
- 18 रक्षित पत्रावली।


(अशुतोष कुमार)

संयुक्त शासन सचिव

30
EE 4286 56737 74

Speed Post under Special Seal



प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (हकएवंलेखा), त्रिपुरा::अगरतला

OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
TRIPURA, AGARTALA - 799006

दूरभाष/Phone-0381-2353905, फ़ैक्स /Fax- 0381-2350103,

ई-मेल/E-mail: agaetripura@cag.gov.in



No Pen-1/Central Govt. Relief/2024-25/ 18270-329

Date :

03 MAY 2024

To

(1) The Pr. A.G. (A&E) / A.G.(A&E) / Other Pension Disbursing authority,
(As per mailing list).

(2) The Treasury Officer,
Agartala Treasury No. 1, Ambassa, Belonia, Bishalgarh, Dharmanagar,
Kailashahar, Knowai & Udaipur of Tripura State.

(3) The Sub Treasury Officer,
Amarpur, Gandacherra, Jirania, Kamalpur, Kanchanpur, Kumarghat,
Longtharai Valley, Mohanpur, Panisagar, Sabroom, Santirbazar, Sonamura of
Tripura State.

Subject: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners -
Revised rate w.e.f. 01/01/2024 regarding.

Sir,

I am to enclose herewith the copy of the Memorandum No.F.42/02/2024-F&PW(D),
dated 13/03/2024 of Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department
of Pension & Pensioners' Welfare regarding Grant of Dearness Relief to Central Government
pensioners/family pensioners - Revised rate @50% of the basic pension/family pension (including
additional pension/family pension) w.e.f. 01/01/2024.

You are, therefore, requested to make payment or arrange to make necessary circulation
under their jurisdiction.

Encls: As stated



11432

15/5/24

Pen(MSC)

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer

Shri Anjan
Deepak
15/5/24



3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date: 13th March, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.01.2024-reg

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/04/2023-P&PW(D) dated 27.10.2023 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of 46% to 50% of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) w.e.f 01st January, 2024.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

- (i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D) Vol. II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
- (ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
- (iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.
- (iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.
- (v) Pensioners who are in receipt of provisional pension.
- (vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. The payment of arrears of Dearness Relief shall not be made before the date of disbursement of pension/family pension of March, 2024.

5. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

Contd./...

-2-

6. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

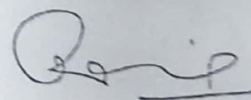
7. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

8. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

9. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

10. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/1/2024-E-II (B) dated 12.03.2024.

Hindi version will follow.


(Ravinder Kumar) 13/3
Director

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

Mailing List

S. Nos	Name of the Office
1.	The Pr. Accountant General(A&E), Maharashtra-I, Maharshi Karva Marg, Mumbai-400020.
2.	The Pr. Accountant General(A&E), Maharashtra-II, West High Court Road, Nagpur-400001.
3.	The Pr. Accountant General(A&E), Jammu & Kashmir, Srinagar-190009.
4.	The Pr. Accountant General(A&E), Jharkhand, Ranchi-834002.
5.	The Pr. Accountant General(A&E)-II, Uttar Pradesh, Sarojani Naidu Marg, Prayagraj/Allahabad-211001.
6.	The Pr. Accountant General(A&E)-I, Uttar Pradesh, Audit Bhaban, Bibhuti Khanda, Gomatinagar, Lucknow-226010.
7.	The Pr. Accountant General(A&E), Haryana, Chandigarh-160047.
8.	The Pr. Accountant General(A&E), Punjab, Sector- II, Chandigarh- 160017.
9.	The Pr. Accountant General(A&E), Assam, Beltola, Guwahati- 781029.
10.	The Pr. Accountant General(A&E), Manipur, Imphal-795001.
11.	The Pr. Accountant General(A&E), Madhya Pradesh-I, Hoshangabad Road, Bhopal, PIN-462011.
12.	The Pr. Accountant General(A&E), Madhya Pradesh-II, Jhansi Road, Gwalior-474002.
13.	The Pr. Accountant General(A&E), Himachal Pradesh, Simla-171003.
14.	The Pr. Accountant General(A&E), Gujrat-II, Ahmedabad-380009.
15.	The Pr. Accountant General(A&E), Gujrat-I, Rajkot-380001.
16.	The Pr. Accountant General(A&E), Rajasthan, Jaipur-302005.
17.	The Pr. Accountant General(A&E), Andhra Pradesh-I, Hyderabad-500004.
18.	The Pr. Accountant General(A&E), Andhra Pradesh-II, Vijayawada-520002.
19.	The Pr. Accountant General(A&E), Nagaland, Kohima-797001.
20.	The Pr. Accountant General(A&E), Karnataka-I, Bangalore-560001.
21.	The Pr. Accountant General(A&E), Karnataka-II, Bangalore-560007.

Contd.



22.	The Pr. Accountant General(A&E), Tamil Nadu, Chennai-600018.
23.	The Pr. Accountant General(A&E), Kerala, M. G. Road, Post Box No.5607, Thiruvananthapuram-695001.
24.	The Pr. Accountant General(A&E), Orissa, Bhubaneswar-751001.
25.	O/o. The Chief Controller of Accounts, Accounts & Treasuries, Government of Mizoram, MINECO, Khatla, Aizawl, PIN-796001.
26.	The Pr. Accountant General(Audit), Sikkim, Gangtok-737101.
27.	The Pr. Accountant General(A&E), West Bengal- Pen-V, Treasury Building, Kolkata-700001.
28.	The Pr. Accountant General(A&E), Meghalaya, Shillong-793001.
29.	The Pr. Accountant General(A&E), Tamilnadu & Pandichery, Chennai-600018.
30.	The Pr. Accountant General(A&E)-II, Bihar, The Pr. Accountant General(A&E), Bihar-II, Gandhi Maidan, Patna-800001.
31.	The Pr. Director of Accounts & Treasuries, Pondicherry, PO- Puducherry, PIN-605001.
32.	The Pr. Director of Accounts & Treasuries, Arunachal Pradesh, Naharlagoon, PIN-791110.
33.	The Pr. Director of Accounts & Treasuries, Mizoram, Aizawl-796001.
34.	The Pr. Accountant General(A&E), Uttarakhand, Dehradun, Pin-248171.
35.	The Major Assistant Military Attache (Pension), Military Pension Branch, Embassy of India, Katmandu, Nepal (Through the Chief Controller of Accounts Ministry of External Affairs, Pension Section, JNB, Janpath, New Delhi-110011).
36.	The Pay and Accounts Officer-V (Pension), Tis Hazari, Delhi- 110054.
37.	Sr. Accounts Officer (Establishment & Pension), O/o the Accountant General (A&E)-II, UP, Audit Bhawan Vibhuti Khand, Gomatinagar, Lucknow (UP), Pin Code-226010.
38.	The Pr. Accountant General(A&E), Telangana, Hyderabad- 500004.
39.	The Pr. Accountant General(A&E), Nagaland, Kohima, Pin-797001,
40.	The Pr. Accountant General(A&E), Chattisgarh, Raipur, Pin-493111.